अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक- 05/10/2020 को अपरान्ह 3:30 बजे नेशनल ब्राडबैण्ड मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ब्राडबैण्ड कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः-

उपस्थितिः- संलग्नानुसार।

सर्वप्रथम बीएसएनएल द्वारा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाये जाने के कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। प्रदेश के कुल 820 ब्लाक में से 667 ब्लाक के स्वीकृत 45359 ग्राम पंचायतों में से 29953 में कार्य हो चुका है तथा अवशेष 15406 ग्राम पंचायत में कार्य प्रगति पर है जिसे पूर्ण करने हेतु माहवार ब्लाकवार योजना उपलब्ध कराई गयी है जिसके अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत ग्राम पंचायतों में 31 मार्च 2021 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्रदेश के कुल 117 ब्लॉकों के 8295 ग्राम पंचायतों में पीपीपी माध्यम से तथा यूपी वेस्ट के 36 ब्लॉकों के 2195 ग्राम पंचायतो में कार्य का अप्रूवल भारत सरकार से प्रतीक्षित है।

2. श्री आशाराम कोमडो जेना, सेलुलर आपरेटर एसोसिएसन आफ इंडिया (सीओएआई) ने यह जानना चाहा कि बीबीएनएल द्वारा फाइबर लेइग हेतु पीपीपी मोड किस प्रकार से लागू किये जाने की योजना है। श्री रावत, वरिष्ठ महाप्रबन्धक, बीबीएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नीति अभी उपलब्ध नही करायी गयी है।

3. ब्राडबैण्ड रेडीनेस इण्डेक्स के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दूरसंचार विभाग को अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा BRI के बिन्दु 15 एवं 20 से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। BRI के बिन्दु 31 से 33 पर प्रदेश की प्रेषित सूचना के सम्बन्ध मे की गई पृच्छा पर दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि प्रदेश में लागू नीति के अनुसार प्रेषित सूचनाये उचित है। प्रदेश में सभी प्रकार के विद्युत कनेक्शन आन लाइन प्रदान किये जा रहे हैं। झटपट पोर्टल से सभी को प्रियारिटी पर कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं। प्रदेश में सभी प्रकार के कनेक्शन सभी जनपदों में प्रियारिटी कनेक्शन है। सभी टैरिफ इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय है।

4. दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आरओडब्लू आवेदनों का ससमय निस्तारण कराने का अनुरोध किया गया। अवगत कराया गया कि आरओडब्लू आवेदनों के ससमय निस्तारण हेतु आरओडब्लू पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल से दिनांक 31/10/2020 तक इन्टीग्रेट कर दिया जायेगा। निवेश मित्र पोर्टल पर नियमित रूप से मानिटरिंग उच्च स्तर से होती है अतः आवेदनों का ससमय निस्तारण हो सकेगा। यह भी अवगत कराया गया कि यह तथ्य संज्ञान में लाये जाने पर कि एनओसी हेतु विकास प्राधिकरणों एवं अन्य निकायों द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी मांगा जा रहा है, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशनों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र सामान्यतः उपलब्ध नही कराया जाता है। रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन का अनापत्ति प्रमाणपत्र अपलोड नहीं करने के कारण राइट आफ वे पोर्टल पर आवेदन निरस्त कर दिये जा रहे हैं। चूंकि रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन का अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगे जाने का भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स में भी

...2

उल्लेख नहीं है, अतः इसकी मांग समीचीन नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आवास विभाग को उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है कि प्रदेश में मोबाइल टावर की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन के अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग शासकीय संस्थाओं द्वारा न की जाये।

5. दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आरओडब्लू आवेदनो का 45 दिन के पश्चात डीम्ड एप्रूवल कराने के अनुरोध पर शासन स्तर से कार्यवाही प्रस्तावित करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

6. जनपद स्तर पर योजना के मॉनिटरिंग हेतु जिला लेबिल कमेटी के गठन हेतु शासनादेश का ड्राफ्ट बीएसएनएल के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को को दिया गया। ड्राफ्ट में यह इंगित करने के निर्देश दिये गये कि बीएसएनएल द्वारा जिला मॉनिटरिंग समिति को जिले के अन्दर ले की गयी आप्टिकल फाइबर का लेआउट उपलब्ध कराया जायेगा जिसे अर्धवार्षिक रूप से अपडेट भी किया जायेगा ताकि केबल कटिंग को रोकने हेतु समन्वय किया जा सके।

7. अवशेष ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाये जाने हेतु हेबिटेशन/सेन्सेस डाटा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा उपरोक्त डाटा ई-मेल से उपलब्ध कराया गया है जिसमें कतिपय कमियों को इंगित करते हुये दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश से परीक्षण कर पुनः अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा डाटा उपलब्ध कराने मे सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान जा रहा है।

8. संयुक्त सचिव (टेलीकॉम), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की दिनांक 31.07.2020 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग बैठक के कार्यवृत्त के विन्दु 4 एवं 15 पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् मत स्थिर किया गया है:-

क. शासकीय भवनों अथवा जिन भवनों में जीपॉन इक्विपमेन्ट स्थापित हैं, वे उचित रूप से मेन्टेन नहीं हैं, के बिन्दु पर भारत सरकार तथा प्रदेश के शासकीय विभागों के द्वारा निर्गत उन शासनादेशों की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिसके आधार पर विभागों को जीपान लगवाने एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गयी थी। जीपान की स्थापना के पश्चात मेन्टीनेन्स आदि में यदि विभागीय शासनादेश मे दिये गये निर्देशों का पालन सम्बंधित विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है तो पूर्व निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु आदेश निर्गत कराने की कार्यवाही की जायेगी।

ख. राज्य सरकार की शासकीय संस्थाओं द्वारा FTTH कनेक्शन लेने हेतु निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। यह कनेक्शन प्रारम्भ में 5 संस्थाओं के लिये एक वर्ष हेतु निःशुल्क है तथा स्थापना भी निःशुल्क है। श्री रावत, महाप्रबन्धक, बीबीएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय संस्थान यथा पंचायती राज विभाग, आगनवाड़ी, हास्पिटल, स्कूल आदि में कनेक्शन देने हेतु प्राइवेट आपेटर के साथ साथ बीएसएनएल भी

उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को चिन्हित कर उनको FTTH कनेक्शन प्राप्त करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश बीबीएनएल को दिये गये।

ग. सीएससी-एसपीवी को निशुल्क पावर कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पावर कनेक्शन कामर्शियल एक्टिविटी होने के कारण निःशुल्क नही प्रदान किया जा सकता है। निःशुल्क पावर कनेक्शन देने हेतु भारत सरकार/नीति आयोग का शासनादेश यदि कोई है, तो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया जिसके आधार पर निर्णय लिया जा सके।

घ. दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि नीति आयोग द्वारा माडल के रूप में जनपद वाराणसी के सेवापूरी ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतो में सभी शासकीय विभागों मे FTTH कनेक्शन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने शासन स्तर से वाराणसी के सेवापूरी ब्लाक में FTTH कनेक्शन प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु यूपीएलसी को निर्देश दिये जाये।

ङ. कुछ आईएसपी/टीएसपी को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं कराने के सम्बन्ध मे दूरसंचार विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। श्री अविनाश, प्रतिनिधि टाईपा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके मेम्बर टावर विजन एवं इन्डस टावर द्वारा टावर एवं पावर के लिये आवेदन किया था परन्तु 6 माह से अधिक समय से आवेदन पेन्डिंग है। आवेदनों में लगभग 26 यूपीईस्ट के तथा 16 यूपीवेस्ट के हैं। लम्बित प्रकरणों की सूची प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये जिससे यूपीपीसीएल से वार्ता कर कनेक्शन प्रदान कराया जा सके। टाइपा के प्रतिनिधि को इन्डस्ट्री के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन यूपी के निवेश मित्र पोर्टल पर करने का सुझाव दिया गया जहॉ आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग होती है।

च. प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा अधिक रिकरिंग चार्जेज लिये जाने के सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया गया कि टाइपा के प्रतिनिधि श्री व्यास से अन्य प्रदेश में लागू प्राविधान प्राप्त करते हुये तथा भारत सरकार से यदि कोई गाइडलाइन जारी की गयी हो, के साथ प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर सम्बंधित विभाग से दरों को युक्तियुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा सके।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

...4

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्याः-1778/78-1-2020-666/2020
लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग एवं
   लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सलाहकार/Sr. DG of DoT of the UP (East) & UP (West) LSAs,
   दूर संचार विभाग, भारत सरकार-(सदस्य संयोजक)
3. CGM BSNL UP (east) and UP(West) telecom Circle
4. CGM BBNL-State Head UP (east) & UP (West)
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
7. निवेश मित्र पोर्टल टीम (उद्योग बन्धु), लखनऊ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव(आर0/एन0), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

नेशनल ब्रॉडबैण्ड मिशन के संबंध में अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05–10–2020 को अपरान्ह 03:30 बजे से लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारीगणः–

क्र. सॅ.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	Rakesh Kumar	DDG	UPE LSA	9868217061	[signature]
2	POORAN MAL	DDG	— " —	9415261206	[signature]
3	YATISH KATHERIA	DDG/DOT	UP(E) LSA	8765200300	[signature]
4	Azam Siddiqui	DIR Rural-2)	U.P.(E) LSA	9113464360	[signature]
5	A.K. Mishra	Director (R-1)	UP(E) LSA DOT	9415011900	[signature]
6	A.K. Shrivastava	General Manager (NOFN) BSNL	BSNL, U.P.(W) Circle	9415205771	[signature]
7	Bhaskar Pandey	J.S.	PWD	9454412214	[signature]
8	Akhilanand Brahmachari	Deputy Secretary	Urban Deptt.	9454413390	[signature]
9	Sandeep Jaiswal	Asst. Director	% Sr DDG UPE	9453016288	[signature]
10	Girjesh Kumar	Under Secretary	Panchayati Raj	9454412074	[signature]

क्र. सँ.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर
11	Prashant Srivastava	Asst. Manager	CSC-SPV	7408921111 Prashant.Srivastava@csc.gov.in	[signature]
12	Avanish K. Singh	General Manager	CSC-SPV	9919998319 avanish.singh@csc.gov.in	[signature]
13	Rakesh Kumar	E.E. P.W.D, Lko	P.W.D, Lko	9454647738 [illegible] @gmail.com	[signature]
14	P.S. SONIL IYER	Web Officer PWD	P.W.D., Lko.	9838999630 [illegible]pwd@gmail.com	[signature]
15	Sita Ram Yadav	Director (DP)	Udyogbandhu	9454411164	[signature]
16	Arvind Kumar Verma	Joint Director State Planning Commission	Planning Deptt.	9454468894	[signature]
17	Manoj Kr. Gupta	Research Officer State Planning Commission	Planning deptt.	9454468938	[signature]
18	Ajay Kumar	State Planner	Panchayati Raj	8920254738	[signature]
19	Saket Kr Verma	DGM-PM & IT	BSNL	9415065657	[signature]
20	Babu Ram	Principal GM	BSNL	9415100027	[signature]
21	NEHA PRAKASH	Spl Secy	IT	9690007639	[signature]